Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

फरवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- स्कूल शिक्षा मंत्री ने 31 शिक्षकों को 'मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण' पुरस्कार से किया सम्मानित 3
- छत्तीसगढ़ में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का नया रिकॉर्ड 3
- छत्तीसगढ़ की टीम को मिला सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर का पुरस्कार 4
- प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हेतु केंद्र व राज्य सरकार करेंगी संयुक्त प्रयास 5
- विधानसभा अध्यक्ष ने पेंड्री गौठान में रीपा का किया शुभारंभ 5
- छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में एवं 2 बाल वैज्ञानिकों ने इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में प्रस्तुत किया अपना शोध परियोजना 5
- राजिम माघी पुन्नी मेला का भव्य शुभारंभ 6
- 'निकलर एप' द्वारा पढ़ाई कराने के लिये छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार 7
- शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा को लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाज़ा गया 7
- देश के आकांक्षी ज़िलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िला शीर्ष पाँच में शामिल 8
- तिरोहित तितुरघाट' पुस्तक का विमोचन 8
- राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन 9
- छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने बिस्वा भूषण हरिचंदन 10
- मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित 10
- छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू 10
- मंच संचालन के लिये कामिनी कौशिक का नाम 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज 11
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात 12
- छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल 13
- कृषि मंत्री ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' कार्यक्रम का शुभारंभ किया 13
- 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 14
- मध्यान्ह भोजन में मिलेट्स को शामिल करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी 14
- छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर जी.एस.टी परिषद की बैठक में ट्रिब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य रखे जाने पर बनी आम सहमति 15
- गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 13 यूनिट शुरू 16
- मुख्यमंत्री ने ई-लाईब्रेरी का किया उद्घाटन 16
- मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय 17
- मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि का किया अंतरण 18
- मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट' व ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल 'एस.डी.जी. डैशबोर्ड' का विमोचन किया 18
- स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा आन-डिमांड बहु-भाषा शिक्षण पर आनलाईन कोर्स का शुभारंभ 19
- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिये ज़िला ग्रंथालय के ई-लाइब्रेरी में 18 लाख रुपए की लागत से बनेगा ई-लाइब्रेरी क्लासरूम 20
- क्रेडा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था एन.आर.डी.सी के साथ किया एम.ओ.यू. 20
- छत्तीसगढ़ के दो अस्पतालों को 'मुस्कान' कार्यक्रम के अंतर्गत मिला एनक्यूएएस प्रमाण पत्र 21
- प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कोंडागाँव के कोकोड़ी में ले रहा आकार 21
- प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में हुआ शुरू 22
- विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की ली शपथ 23
- डॉ. ममता चंद्राकर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 23
- 'दिशा' स्कीम के तहत शार्ट फिल्म प्रतियोगिता 24
- राज्य के सभी रीपा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र 24
- 6 दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ 25
- 21वाँ अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 25

नोट :

छत्तीसगढ़

स्कूल शिक्षा मंत्री ने 31 शिक्षकों को 'मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण' पुरस्कार से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर स्थित संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा कार्यालय के सभागार में 'मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण' योजना के अंतर्गत रायपुर संभाग के 31 शिक्षकों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इनमें शिक्षा दूत सम्मान से 12 शिक्षक, ज्ञानदीप से 03 शिक्षक, शिक्षा श्री से 03 व्याख्याता, उत्कृष्ट प्राचार्य 05 और 08 उत्कृष्ट प्रधान पाठक सम्मानित हुए।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने समारोह में विकासखंड स्तर पर कक्षा पहली से पाँचवी तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शिक्षा दूत पुरस्कार में 5 हज़ार रुपए, ज़िला स्तर पूर्व माध्यमिक शाला के कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन करने वालों शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार में 7 हज़ार रुपए, संभाग स्तर पर कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शिक्षा श्री पुरस्कार में 10 हज़ार रुपए की सम्मान राशि के साथ ही प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये।
- उन्होंने इसके साथ ही ज़िला अंतर्गत अपने विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्यों को 2 हज़ार रुपए, विकासखंड स्तर पर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान पाठकों को एक-एक हज़ार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। सभी सम्मानित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया गया।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार प्रतिवर्ष विकासखंड, ज़िला और संभाग स्तर पर मुख्यमंत्री गौरव अंलकरण योजना के अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है।
- विकासखंड स्तर पर शिक्षक दूत, ज़िला स्तर पर ज्ञानदीप और संभाग स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान से 'मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण'योजना के तहत् शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।
- यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को बच्चों के अध्ययन-अध्यापन के साथ कौशल विकास, बौद्धिक, शारीरिक एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व के लिये प्रेरणादायक कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है।
- स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी की अवधि में शिक्षकों ने शिक्षा की ज्योति को जलाए रखा और बहुत सारे नवाचार किये। राज्य के शिक्षकों द्वारा उस दौरान किये नवाचारों का अनुकरण अन्य राज्यों ने भी किया।

छत्तीसगढ़ में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का नया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी की अंतिम तिथि तक 107 लाख 51 हज़ार 858 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा राज्य है, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से यदि देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है।

नोट :

- राज्य में 23 लाख 41 हज़ार 935 किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से यह आँकड़ा इतना ज्यादा है कि देश के अन्य राज्य इसके आसपास भी नहीं हैं।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीते चार सालों में धान खरीदी की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ और बेहतर किया गया है कि किसानों को धान बेचने और भुगतान प्राप्त करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। यही वजह है कि बीते चार सालों में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों किसानों की संख्या और धान खरीदी की मात्रा में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सेंट्रल पूल में धान के योगदानकर्त्ता राज्य के रूप में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य में कृषि और किसान दोनों समृद्ध हुए हैं। राज्य में धान खरीदी के आँकड़े में साल-दर-साल की रिकॉर्ड वृद्धि और 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'के तहत प्रति एकड़ के मान से उत्पादक कृषकों को 9 हज़ार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है।
- इस साल राज्य में 249 नई राईस मिलें स्थापित हुई हैं, जिसके कारण राज्य में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने के लिये पंजीकृत मिलर्स की संख्या 2035 से बढ़कर अब 2284 हो गई है।
- बीते चार सालों में कृषि के क्षेत्र में समृद्धि और किसानों की खुशहाली का ही परिणाम है कि राज्य में टैक्टर खरीदने वाले ग्रामीणों और किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राज्य में चार सालों में किसानों ने 80 हज़ार से अधिक ट्रैक्टर की खरीदी की है।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में धान खरीदी के लिये खरीदी केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ ही पंजीकृत किसानों से धान खरीदी के लिये मैन्यूअल टोकन के साथ-साथ ऑनलाईन टोकन जारी करने की व्यवस्था 'टोकन तुहंर हाथ' एप के माध्यम से किसानों को धान विक्रय के लिये बेहतर व्यवस्था की गई है।
- राज्य में धान खरीदी शुरूआती दिन 1 नवंबर, 2022 से लेकर आखिरी दिन यानि 31 जनवरी, 2023 तक निर्बाध रूप से जारी रही। राज्य में 98 लाख पंजीकृत किसानों और 32.19 लाख हेक्टेयर रकबा को देखते हुए इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान था।
- खाद्य सचिव टी.के. वर्मा ने बताया कि राज्य में बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिये खरीदी केंद्रों से मिलर्स द्वारा सीधे धान का उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिसके चलते अब तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है।
- उन्होंने बताया कि धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिये धान के उठाव की व्यवस्था के चलते इस साल बमुश्किल 3 लाख मीट्रिक टन धान ही संग्रहण केंद्रों में ले जाना पड़ेगा, जबकि बीते साल लगभग 23 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों ले जाने की जरूरत पड़ी थी। धान का उठाव की इस व्यवस्था के चलते लगभग 150-200 करोड़ रूपए की बचत होगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कस्टम मिलिंग के लिये मिलर्स को दी जानी वाली प्रोत्साहन राशि को प्रति क्विंटल के मान से 120 रुपए दिये जाने से भी कस्टम मिलिंग में तेजी आई है। इस साल 249 नये मिलर्स ने पंजीयन कराया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि धान से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण को गति मिली है, इससे रोज़गार के नये अवसर भी सृजित हुए हैं।
- राज्य सरकार की किसान हितैषी नीति और फैसलों के चलते धान का रकबा बढ़कर 19 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पंजीकृत किसानों में 2.32 लाख नये किसान शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ की टीम को मिला सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

1 फरवरी, 2023 को सिकंदराबाद के केआईएमएस अस्पताल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कान, नाक और गला (ईएनटी) विभाग की टीम को 'सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार' मिला।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभागाध्यक्ष डॉ. हंसा बंजारा ने बताया कि ईएनटी विभाग के ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की टीम ने माता-पिता द्वारा प्रत्यारोपण की देखभाल पर एक पोस्टर प्रस्तुति दी।

नोट :

- वैज्ञानिक पोस्टर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत संचालित कॉक्लियर इम्प्लांट स्वास्थ्य सहायता (Cochlear implant health assistance) पर आधारित था।
- सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन (TASLPA) और इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑफ ऑडियोलॉजिकल मेडिसिन (ISAM) द्वारा किया गया था।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हेतु केंद्र व राज्य सरकार करेंगी संयुक्त प्रयास

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को संचालनालय पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्द्धन हेतु परस्पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौते में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पुरा-संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी।
- इसके अलावा दोनों संस्थाओं की विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों-परियोजनाओं, जैसे शोध प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का संकलन, सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा राज्य संरक्षित शैलाश्रयों के संरक्षण-परिरक्षण जैसे कार्यों में सहायक होगी।
- इस अवसर पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 'छत्तीसगढ़ की धरोहरों'और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में यह समझौता ज्ञापन महत्त्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तुओं को सहेजने के लिये प्रतिबद्ध है।

विधानसभा अध्यक्ष ने पेंड्री गौठान में रीपा का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जांजगीर-चांपा ज़िले के अंतर्गत पेंड्री गौठान में रीपा योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा अध्यक्ष ने रीपा योजना के तहत गौठान में पूजन सामग्री यूनिट, कोसा यूनिट, मशरूम यूनिट का शुभारंभ करते हुए संबंधित हितग्राहियों से उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के विषय में चर्चा की।
- जांजगीर-चांपा ज़िले में रीपा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोज़गार से जोड़ने हेतु शेडयुक्त आजीविका गतिविधियों की शुरूआत की गई है। इससे ग्राम पेंड्री सहित आस-पास की महिलाएँ एवं युवाओं को स्वरोज़गार मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन सभी ज़िलों में प्रदेश स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना (रीपा) का शुभारंभ किया गया था।

छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में एवं 2 बाल वैज्ञानिकों ने इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में प्रस्तुत किया अपना शोध परियोजना

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै ने बताया कि प्रदेश के 16 बाल वैज्ञानिकों ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में एवं 2 बाल वैज्ञानिकों ने इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में अपने शोधकार्य को प्रस्तुत किया, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा खूब सराहना मिली।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक गुजरात कौंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के अन्य राज्यों से लगभग 1200 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
- अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै ने बताया कि 16 बाल वैज्ञानिकों में से 12 लड़कियों का चयन हुआ है। लड़कियों का चयन इस बात को दर्शाता है कि लड़कियाँ विज्ञान और शोधकार्य में भी बढ़-चढ़ कर भाग ले रहीं है। इससे समाज में भी एक सार्थक संदेश जाएगा।
- राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस 2022 में पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य और कल्याण तथा पाँच उपविषयों- अपने पारिस्थितिकी तंत्र को जानें, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ, आत्मनिर्भरता के लिये पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिये तकनीकी नवाचार पर शोधकार्य प्रस्तुत किया गया।
- राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में छत्तीसगढ़ से प्रियांश भादुड़ी, नंदिता केवट, रूपशिखा साहू, दिशा साहू, प्रियांशु पटेल, राधिका कँवर, भूमिका जोशी, करम सैमुअल, महेश्वर साहू, जाह्नवी ठाकुर, किरण कंवर, खुशी झा, मनोहर बघेल, प्रार्थना केवट, अन्विका गुप्ता एवं अनन्या सिंह ने भाग लेकर शोध परियोजना प्रस्तुत किया।
- इसके अलावा बाल वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने टीचर्स वर्कशॉप, मीट ऑफ साइंटिस्ट सेशन, लोकप्रिय विज्ञान वार्ता, प्रदर्शनी, गतिविधि शिविर, पोस्टर प्रस्तुती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
- राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में वैज्ञानिक डॉ. जे.के. राय एवं चार शिक्षकों अनिल तिवारी, जगदीश्वर राव, मीना जॉनसन और सीमा चतुर्वेदी ने भाग लेकर बाल वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन किया।
- इसके अलावा राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस से चयनित दो बाल वैज्ञानिक अनमोल मालवीय और कुमारी हर्षिता राठिया ने नागपुर, महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी को आयोजित 108 वीं इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में अपना शोध परियोजना को प्रस्तुत किया था।
- इसके साथ हीं इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में प्राईड ऑफ इंडिया-मेगा साइंस एक्स्पो में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों डॉ. जे.के. राय और डॉ. बीना शर्मा एवं दो परियोजना स्टाफ द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की विभिन्न गतिविधियों को प्रादर्श के माध्यम से प्रस्तुत किया।

राजिम माघी पुन्नी मेला का भव्य शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाले राजिम में माघी पुन्नी मेला का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यह मेला 18 फरवरी (महाशिवरात्रि) तक जारी रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजिम के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालुओं ने माघी पुन्नी का पुण्य स्नान किया। स्नान करने हेतु पूरे देश सहित प्रदेश के कोने-कोने से लोग पहुँचे और गंगा घाट में डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाले राजिम में चित्रोत्पला गंगा (महानदी), पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सदियों से यह माघी पुन्नी मेला लगता है, जो माघी पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है।
- माघी पूर्णिमा के दिन को भगवान श्री राजीव लोचन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में सदियों से राजिम के इस पावन भूमि में मेला लगता आ रहा है।
- 18 फरवरी (महाशिवरात्रि) तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या के तहत छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे।

नोट :

'निकलर एप' द्वारा पढ़ाई कराने के लिये छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

5 फरवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में 'निकलर एप'द्वारा पढ़ाई कराने के लिये सी.एस.आई. ने छत्तीगसढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाज़ा है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड 25 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को परियोजना श्रेणी के तहत् 20वें सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिये प्रस्तुत 'इनोवेटिव असेसमेंट टूल-एनआईसीलर' (पीआरजे 22008) का नामांकन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चुना गया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर, 2022 को लॉन्च किये गए सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम में भी स्कूलों का आकलन निकलर एप के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकेगा। इसके लिये भी शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है।
- निकलर एप का उपयोग शिक्षकों के कार्यों को आसान करने हेतु किया जाता है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और एन आई सी ने भी शिक्षकों के आकलन संबंधी कार्य को आसान करने के लिये लंबी रिसर्च करते हुए निकलर एप का निर्माण किया है।
- एप के उपयोग के लिये सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाकर निकलर एप को डाउनलोड करना होता है। स्कूल के यू-डाइस के आधार पर पोर्टल से विद्यार्थियों के लिये क्यू आर कोड वाले कार्ड डाउनलोड कर उसे एक पुठ्ठे में चिपकाना पड़ता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये इस प्रकार से एक यूनिक कार्ड उनके नाम से देना होता है। इसे आपस में बदलना नहीं चाहिये। यह उस बच्चे के नाम से उसके पास पूरे सत्र में रहना चाहिये।
- किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछना हो तो निकलर एप में उस पाठ से संबंधित उपलब्ध प्रश्न निकालकर पूछ सकते हैं या फिर स्वयं अपने प्रश्न दे सकते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न के चार विकल्प होने चाहिये। बच्चों को सही विकल्प के आधार पर कैसे कार्ड को पकड़ना है यह सिखाना होगा।
- निकलर एप का उपयोग कर बच्चों की उपस्थिति भी ली जा सकती है। इस एप के माध्यम से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों के ऑडियो बनाकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एप के उपयोग में कुछ भी दिक्कत आती है तो शिक्षकों के बीच से ही तकनीकी रूप से विशेषज्ञ शिक्षक वीडियो बनाकर सहायता करते हैं, जिससे कक्षा में इसको क्रियान्वित करना आसान हो गया है।
- समग्र शिक्षा की ओर से इस एप के उपयोग हेतु निरंतर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष सभी स्कूलों को इंटरनेट के लिये बजट भी उपलब्ध करवाया गया है। शिक्षकों को निकलर एप के उपयोग के लिये प्रशिक्षित भी किया गया है।

शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा को लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाज़ा गया

चर्चा में क्यों ?

6 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरिया ज़िले की शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा के सहायक शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिये 4 फरवरी को नई दिल्ली में 'आस एक प्रयास'ट्रस्ट द्वारा लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाज़ा गया।

प्रमुख बिंदु

- सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और आचार्य प्रद्युम्न (योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु) ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।
- 'आस एक प्रयास' संस्था द्वारा हर वर्ष देशभर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मानवता एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाता है।
- 'नीली छतरी वाले गुरुजी' के नाम से विख्यात शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा ने कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई से जोड़े रखा। उनकी कहानी सभी को प्रेरणा देती है कि जीवन को कैसे महान बनाया जा सकता है।

नोट :

- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौरान उन्होंने सोचा कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो क्यों न स्कूल को ही बच्चों तक ले जाया जा सके। तब उन्होंने अपनी मोटर साइकिल पर घंटी, ग्रीन बोर्ड, छोटा सा पुस्तकालय और नीली छतरी सजाकर गाँव के एक मोहल्ले में बच्चों को बिना एक दूसरे से संपर्क बनाए पढ़ाना शुरू किया तब से इनका नाम 'नीली छतरी वाले गुरुजी' भी पड़ा।
- कोरोना काल में बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जोड़े रखने की यह सुरक्षित तरीका प्रधानमंत्री को भी भाया। उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया। शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पहुंच विहीन और नेटवर्क रहित क्षेत्रों के लिये सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में 'मोहल्ला क्लास' का कॉन्सेप्ट दिया, जो आगे चलकर देशभर में काफी चर्चित और लोकप्रिय हुआ।
- शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा ने सुदूर वनांचल ग्राम सकड़ा के प्राथमिक शाला का शासन एवं समाज के सहयोग से कायाकल्प कर उसे एक आदर्श स्कूल के रूप से स्थापित किया।
- शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा अनुभव आधारित शिक्षण पर ज़ोर देते हैं और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने का प्रयास करते हैं, उनके विद्यालय पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसका प्रदर्शन एससीईआरटी और एनसीईआरटी में भी किया गया है। विगत वर्षों में इनके विद्यालय के कई बच्चों का चयन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हुआ है।
- शिक्षक रुद्रप्रताप सिंह राणा 'निपुण भारत अभियान' के तहत एफएलएन के 5 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। उन्होंने एनसीईआरटी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रस्तुति भी दी है। 'लाईफ्स रियल हीरो'पुस्तक में उनके जीवन के ऊपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है, जो सभी कर्मठ शिक्षकों को प्रेरित एवं गौरवान्वित करता है।

देश के आकांक्षी ज़िलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िला शीर्ष पाँच में शामिल

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी 2023 को नीति आयोग की ओर से दिसंबर, 2022 के लिये जारी आकांक्षी ज़िलों की रिपोर्ट 'चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग' में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िला शीर्ष पाँच ज़िलों में चौथे स्थान पर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में देश में घोषित 112 आकांक्षी ज़िलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष पाँच ज़िलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िला चौथे स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर ज़िले का स्थान तीसरा है।
- नारायणपुर ज़िले का स्वास्थ्य और पोषण में स्कोर 72.5 तथा शिक्षा में 57.5 स्कोर है। वहीं सभी क्षेत्रों का समग्र स्कोर 53 हैं।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार वर्षों के भीतर स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में हुए इन प्रयासों को भारत सरकार ने भी कई बार सराहा है।
- राज्य सरकार ने बच्चों में कुपोषण दूर करने और किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एनिमिया से मुक्त करने के लिये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से पोषण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई-दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना का संचालन करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोगों तक डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुँचाए जा रहे हैं।

तिरोहित तितुरघाट' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोविंद पटेल की 'तिरोहित तितुरघाट'पुस्तक का विमोचन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक का संपादन गोविंद पटेल ने किया है तथा भूमिका पुरातत्त्वाविद् प्रभात सिंह ने लिखी है। यह पुस्तक धमधा के तितुरघाट में दो दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्त्विक साक्ष्य और उनकी विशेषता पर आधारित है।
- धर्मधाम गौरवगाथा समिति ने तितुरघाट के तिरोहित (भुला दिये गए) तालाब को फिर से ढूंढा और श्रमदान व जनसहयोग से उसकी फिर से खुदाई की। इस स्थान की प्राचीनता व ऐतिहासिकता के साथ ही तालाब के महत्त्व को दर्शाने के लिये इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
- इस पुस्तक में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित 500 साल पुराने चतुर्भुजी तितुरघाट गाँव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई गई है। यह गाँव अब वहाँ से उजड़ गया है, परंतु गाँव का ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक महत्त्व दर्शाने वाले सौ से अधिक शिलाखंड, स्थापत्य खंड वहाँ बिखरे पड़े हैं, जिनमें तीन शिलालेख और दो दर्जन सती स्तंभ मिले हैं। यहाँ एक मंदिर और तालाब भी थी। धर्मधाम गौरवगाथा समिति ने इस विलुप्त तालाब का पुनर्निर्माण करवाया।
- उल्लेखनीय है कि गोविंद पटेल इससे पहले टमाटर की बंपर पैदावार, तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने, छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी और छः कोरी छः आगर, तरिया अऊ बूढ़वा नरवा नाम की पुस्तिका का प्रकाशन कर चुके हैं।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सह कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 37(6) में निहित प्रावधान के अंतर्गत परिनियम 18 की धारा 1, 8, व 12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अनुमोदित संशोधन के अनुसार परिधिनियम 18 की धारा 1 में उपबंधित उपधारा (a),(b),(c) के उपरांत (d) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी भी महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त करने अथवा मान्यता जारी रखने के लिये निर्धारित आवेदन के पूर्व विश्वविद्यालय को देय बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
- इसी प्रकार धारा 8 के उपधारा 1 में कंडिका (a) तथा (b) के पश्चात (c) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पिछले दो या दो से अधिक वर्षों में जिन संस्थानों के द्वारा सुचारू संचालन के लिये कमियों को दूर नहीं किया गया है, उन्हें दंडित किया जाएगा तथा दंड का निर्धारण कार्य परिषद निर्धारित करेगा।
- इसके साथ ही परिनियम 18 की धारा 12 में उपबंधित उपधारा 1 से 7 के उपरांत 8 जोड़ा गया है।
- इसके अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में विश्वविद्यालय के परिनियम 19 के अंतर्गत स्वीकृत कुल कैडर के 60% फैकल्टी/शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिये। उक्त 60% की बाध्यता को कार्य परिषद द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है।
- इस अवसर पर राज्यपाल उइके ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भिलाई के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरू आडिट कोर्स से संबंधित संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन किया।
- राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अध्यादेश क्रमांक-35 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया है।
- इस संशोधन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों इंजिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए., टाउन प्लानिंग आदि में ऑडिट कोर्स को शामिल किया गया है।
- उक्त संशोधन के उपरांत अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय क्रेडिट अंकों पर आधारित विभिन्न विषयों में ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा प्रदान करेगा। यह कोर्स सी.एस.वी.टी.यू. के मानकों पर आधारित होंगे जो सभी विश्वविद्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे।

नोट :

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने बिस्वा भूषण हरिचंदन

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया है। वह प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल अनुसुइया उइके का स्थान लेंगे।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और 13 राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त किया है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है।
- विदित है कि 84 वर्षीय बिस्वा भूषण हरिचंदन ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं।
- बिस्वा भूषण हरिचंदन ने 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, जिसके बाद 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक वे जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव रहे। इसके साथ ही हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे।
- 1980 से 1988 तक वे बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम किया।

मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण से उत्कृष्ट शिक्षकों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के तहत राज्य शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसंतपुर के शहीद विनोद चौबे मेमोरियल ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत राजनांदगाँव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान-गंडई-खैरागढ़ ज़िले के 9 विकासखंड के 30 शिक्षकों का सम्मान किया गया।
- इसमें ज्ञानदीप पुरस्कार वर्ष 2022 से छुरिया विकासखंड के शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला बूचाबोटा सुंदरलाल साहू, राजनांदगाँव विकासखंड के शिक्षक एल.बी पूर्व माध्यमिक शाला बधेरा की शिक्षिका मधुलिका विश्वकर्मा एवं खैरागढ़ विकासखंड के शिक्षक एल.बी पूर्व माध्यमिक शाला संडी की शिक्षिका निहारिका झा को श्रीफल, शॉल एवं सम्मान के रूप में 7 हज़ार रुपए प्रति शिक्षक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
- साथ ही शिक्षादूत पुरस्कार वर्ष 2022 में कुल 27 शिक्षक को सम्मानित करते हुए 5 हज़ार रुपए प्रति शिक्षक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 27 शिक्षकों को कुल 1 लाख 35 हज़ार रुपए का भुगतान किया गया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में माना पी.टी.एस. परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- तीन दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पुलिस संभागों के खिलाड़ियों के लिये इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राज्य बनने के बाद यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिये किया जा रहा है।

नोट :

- खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के रायपुर, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, छसबल मध्य संभाग, छसबल बिलासपुर, छसबल बस्तर, प्रशिक्षण पीटीएस माना, पीटीएस राजनांदगाँव, पुलिस मुख्यालय, रेडियो, रेल एवं एपीटीएस जगदलपुर, बोरगाँव और सीटीजेडब्ल्यू कांकेर सहित 10 संभागों के लगभग 715 खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया।
- इस अवसर पर महिला और पुरूषों के लिये 100 मीटर दौड़ के आयोजन के साथ-साथ हीट तथा डॉग शो, घुड़सवारी, फेन्सिंग खेल का आयोजन भी किया गया।
- तीन दिवस तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता में टीम गेम्स कबड्डी (पुरूष एवं महिला वर्ग), फुटबाल, व्हालीवाल, हैंडबाल, बास्केटबाल, हॉकी, खो-खो (पुरूष एवं महिला वर्ग), रस्साखींच और एथलेटिक्स में 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500 मी, 300 मी, 5000 मी, 10000 मी, लांग जम्प, हाई जम्प, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, गेड़ी दौड़ तथा बैंडमिंटन (पुरूष एवं महिला वर्ग), टेबल टेनिस का आयोजन पुलिस लाईन रायपुर, कोटा स्टेडियम रायपुर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर, पं.रवि शंकर युनिवर्सिटी ग्राउंड में किया जाएगा।
- इस खेल महोत्सव से पुलिस विभाग के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।

मंच संचालन के लिये कामिनी कौशिक का नाम 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने धमतरी नगर की महिला कामिनी कौशिक को एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम संचालन के लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सर्टिफिकेट, मैडल, लोगो और टी-शर्ट प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि कामिनी कौशिक ने विशेष अवसरों, जैसे आध्यात्मिक, धार्मिक, समाज सेवा, साहित्य, राजनीति, ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पारिवारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद आदि पारिवारिक, सामुदायिक, सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव एवं श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठियों आदि शासकीय एवं गैर शासकीय आयोजनों व अवसरों में सतत् सफलतापूर्वक एंकरिंग (मंच का संचालन) किया है। इसके लिये कामिनी कौशिक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है।
- धमतरी ज़िले की मंच संचालिका कामिनी कौशिक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही मंच संचालन करने में पारंगत हैं। कामिनी धमतरी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाती है। इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिये लगभग 1500 साक्ष्य प्रस्तुत किये थे।
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (GBWR) एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बुक है। इस रिकॉर्ड बुक का उद्देश्य उन लोगों को एक मंच देना है जिनमें कुछ छिपी प्रतिभा है, जो दूसरों से आगे खड़े होना चाहते हैं और अद्वितीय प्रयास करके इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं।
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर में ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के लिये अद्वितीय उपलब्धियों को पहचानने और प्रकाशित करने के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड न केवल किसी व्यक्ति /संगठन को रिकॉर्ड तोड़ने का प्रमाण पत्र देता है बल्कि आम आदमी को कई रिकॉर्ड भी सुझाता है जिसे वे तोड़ सकते हैं और इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं।
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के साथ पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक गतिविधियों को करने के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSRs) के लिये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है, जो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और नए उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिये भी उपयोगी है।

नोट :

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगात

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु लगभग 1 हज़ार करोड़ रूपये राशि देने की घोषणा के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की तथा उत्कृष्ट कार्य हेतु नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों हेतु लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की।
- उन्होंने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई-चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगाँव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगाँव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की।
- इसके साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र, रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम, भूमि विकास नियम का सरलीकरण, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम का उन्नयन, सड़क निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं को रोज़गार प्रदान करने हेतु रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे।
- छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की घोषणा की।
- नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इज़ाफा हो, इसके लिये उन्होंने नगर निगमों में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाने की घोषणा की जिसमें बीपी, सुगर, ब्लड टेस्ट की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी, आधुनिक शौचालय और विकास व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि को 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह में विभिन्न विभागीय योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया।
- 'मुख्यमंत्री मितान योजना'में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये नगर निगम बीरगाँव को सर्वाधिक सक्रिय निकाय, नगर निगम भिलाई चरोदा को व्यापक कवरेज के लिये तथा नगर निगम अंबिकापुर को नगरीय निकाय से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिये पुरस्कृत किया गया।
- 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना'में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये नगर निगम धमतरी, नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा तथा नगर पंचायत आमदी को पुरस्कृत किया गया।
- 'श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना'में बेहतर प्रदर्शन के लिये नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद गरियाबंद तथा नगर पंचायत गुरुर को पुरस्कृत किया गया।
- अधिकतम राजस्व वसूली के लिये नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिका परिषद दीपका एवं नगर पंचायत खरोरा को पुरस्कृत किया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव समागम समारोह अवसर पर विगत 4 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों पर आधरित कॉफी टेबल बुकलेट का विमोचन किया। उन्होंने विभागीय उपलब्धियों पर आधारित वीडियो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर प्रदर्शन मोर सम्मान मार्गदर्शिका का विमोचन, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत एस्पिरेशनल टॉयलेट डिजाइन हेतु मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत खुशियों का आशियाना थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में चयनित हितग्राहियों को पुरस्कार वितरित किये।

नोट :

छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस मिलेट कार्निवाल में भारत के नामी-गिरामी शेफ मिलेट के नए-नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को परोसेंगे।
- कार्निवाल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ और आईआईएमआर हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय सुभाष स्टेडियम में होगा। इस अनूठे कार्निवाल में विशेष रूप से मिलेट फूड कोर्ट होगा, जहाँ आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे।
- मिलेट कार्निवाल का उद्देश्य मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने तथा इसके पोषक मूल्य के प्रति जनजागरूकता लाना है।
- इस आयोजन में प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ मिलेट की विशेषताओं को साझा करने के लिये राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी। साथ ही मिलेट की मांग पैदा करने के लिये मिलेट स्टार्ट-अप अपने पैकेज्ड मिलेट उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।
- इसके अलावा मिलेट की खेती के पर्यावरणीय लाभों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक और स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा के पश्चात् छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी, 2022 को 'मिलेट मिशन' की शुरुआत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में आईसीएआर-आईआईएमआर एवं 14 ज़िलों के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर से हुई थी।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी तथा रागी का क्रय करने का भी निर्देश दिया गया। इसी अवसर पर लघु वनोपज संघ ने भी आईसीएआर से अनुबंध किया जिसके तहत आईआईएमआर मिलेट मिशन के नॉलेज पार्टनर बने।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ कोदो, कुटकी 30 रुपए प्रति किलो और रागी 77 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है।
- सीएसआईडीसी ने मिलेट आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ चुंनिदा ब्लाक में भूमि, संयंत्र एवं उपकरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना पेश की है।
- राज्य केबिनेट ने मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये 'राजीव गांधी न्याय योजना' के अंतर्गत प्रति एकड़ 9 हज़ार रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कोदो, कुटकी एवं रागी की खेती करने पर यह राशि किसानों को दी जाएगी।
- राज्य में मिलेट उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिये, पीडीएस, आंगनबाड़ी एवं मिड डे मील में मिलेट उत्पादों को शीघ्र ही शामिल करने की योजना है।
- पिछले एक साल में मिलेट मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतत: छत्तीसगढ़ को भारत का मिलेट हब बनाने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ही साल 50 हज़ार क्विंटल से अधिक मिलेट का क्रय किया गया है, इस वर्ष अब तक 38 हज़ार क्विंटल कोदो, कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। राज्य के 10 ज़िलों में 12 लघु मिलेट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ ही किसानों को मार्केट में भी अब रुपए 12-15 प्रति किलो की अपेक्षा रुपए 20-25 प्रति किलो का क्रय भाव मिल रहा है। कांकेर ज़िले में 5000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता की एशिया की पहली मिलेट प्रसंस्करण इकाई शुरू हो चुकी है।

कृषि मंत्री ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने निवास कार्यालय में 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' कार्यक्रम का, किसानों को पॉलिसी का वितरण कर शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी गई।
- इसके साथ ही 15 फरवरी से ज़िला स्तर पर सांसद, विधायक या कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों को कुल 2 लाख 23 हज़ार 873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल 13 हज़ार 487 कृषकों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा वितरित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत विपरीत मौसमीय परिस्थितियों से फसल हानि की आर्थिक सुरक्षा के लिये व्यापक फसल बीमा आवरण प्रदान किया जाता है, इन योजनाओं में अनाज, दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया है।
- अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिये योजना स्वैच्छिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 06 करोड़ के बदले दावा राशि 6235.24 करोड़ रुपए का भुगतान पात्र कृषकों को किया गया है।
- मौसम रबी वर्ष 2021-22 अंतर्गत कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 17.90 करोड़ रुपए के विरूद्ध राशि 382.10 करोड़ रुपए का दावा भुगतान कृषकों को किया गया है।

79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगाँव के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 के समापन समारोह में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगाँव में फ्लड लाईट और पवेलियन बनाने के लिये 2 करोड़ रुपए की घोषणा की।
- गौरतलब है कि 8 फरवरी से 16 फरवरी, 2023 तक हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगाँव के अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में दिग्विजय स्टेडियम समिति व आयोजन समिति की ओर से 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23का आयोजन किया गया।
- देश भर में प्रतिष्ठित महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में देश भर से 20 टीमों ने हिस्सा लिया।
- प्रतियोगिता का फाइनल मैच पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली और सेल अकादमी राऊरकेला के बीच खेला गया, जिसमें पेट्रोलियम प्रमोशन पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने सेल अकादमी राऊरकेला को 7-1 गोल से पराजित करते हुए 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा जमाया।
- विजेता टीम को विशाल रजत कप के साथ 2 लाख 51 लाख रुपए, उप-विजेता टीम को रजत कप एवं 2 लाख रुपए नगद, मैन ऑफ द मैच देवेंद्र वाल्मीकि को 51 हज़ार रुपए नगद, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कार्बिल लकरा को 11 हज़ार रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

मध्यान्ह भोजन में मिलेट्स को शामिल करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

18 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्र की मंजूरी के पश्चात् अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 ज़िलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में चार दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किये जाएंगे।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय ने केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य सामग्री वितरित किये जाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर, पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में मिलेट्स के उत्पादन के लिये किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके अलावा मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9 हज़ार रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है।
- गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 ज़िलों में बच्चों को पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 55 दिनों के लिये सोया चिक्की प्रदान करने के लिये केंद्रांश के रूप में 1787.20 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में 1198.14 लाख रुपए इस प्रकार कुल 2995.34 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर जी.एस.टी परिषद की बैठक में ट्रिब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य रखे जाने पर बनी आम सहमति

चर्चा में क्यों ?

18 फरवरी, 2023 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जी.एस.टी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से ट्रिब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य (एक राज्य और एक केंद्र) रखे जाने के प्रस्ताव पर परिषद में आम सहमति बनी।

प्रमुख बिंदु

- इससे सहकारी संघवाद का समुचित ध्यान रखते हुए राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। राज्यों को उनके भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर ट्रिब्यूनल के बेंच की संख्या का निर्धारण का अधिकार भी होगा।
- विदित है कि जी.एस.टी. परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व अन्य राज्यों के वित्तमंत्री, अधिकारीगण तथा छत्तीसगढ़ आयुक्त, वाणिज्यिक कर भीम सिंह भी शामिल हुए।
- यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा रखा गया था। छत्तीसगढ़ द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि शीघ्र प्रदान करने की मांग की गई। केंद्र शासन द्वारा 505 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि तत्काल दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- बैठक में मुख्य मुद्दा जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) का रहा। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन के प्रकरण में टीएनजीएसटी के ट्रिब्यूनल संबंधी प्रावधान को अवैधानिक घोषित करने के पश्चात् अधिकरण संबंधी प्रावधान पर पुनर्विचार हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया था। इस मंत्री समूह का प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत किया गया।
- तेंदूपत्ता पर जी.एस.टी. की दर को शून्य करने के उड़ीसा के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। पूर्व में परिषद की 22वीं एवं 37वीं बैठक में दर अपरिवर्तनीय रखने के निर्णय एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अभिमत के आधार पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश भर में सर्वाधिक लाभ प्रदान किया जाता है। अधिकतम लाभ अंतरित किये जाने से कर का भार संग्राहको को वहन नही करना पड़ता है साथ ही तेंदूपत्ता पर आरसीएम (रिवर्स चार्ज) होने से भी कर का भार शासन द्वारा वहन किया जाता है।
- भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कर का भुगतान करने के पश्चात् खरीदे गए खाद, कृषि यंत्र आदि पर ऐसे आगत कर किसानों को भी देने (जैसा कि अन्य निर्माताओं को दिया जाता है) का प्रस्ताव दिया गया।
- गौरतलब है कि आगत कर की पात्रता, पंजीयन एवं कर योग्य विक्रय होने पर ही होती है। पंजीयन एवं कर योग्य विक्रय नही होने पर किसानों की आगत कर की पात्रता नहीं हैं। अत: छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रस्ताव को रूपांतरित कर किसानों द्वारा उपयोग किये जा रहे समस्त सामग्रियों को जी.एस.टी. से सरकार मुक्त रखने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा गया, जिसे विचारार्थ फिटमेंट कमिटी को प्रेषित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।

नोट :

गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 13 यूनिट शुरू

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये 13 यूनिटें शुरू हो चुकी हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया जा रहा है।
- फिलहाल 21 ज़िलों के 32 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना अंतिम चरण में है, जहाँ शीघ्र ही प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने लगेगा।
- गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये कुल 45 पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 13 की स्थापना पूरी कर वहाँ उत्पादन शुरू कर दिया गया है।
- रायपुर ज़िले में 2 यूनिट स्थापित हुई हैं, जबकि कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोण्डागाँव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर एवं बस्तर ज़िले में 1-1 यूनिट स्थापित एवं क्रियाशील हो चुकी है।
- क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 30,218 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 14,358 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 29 लाख 70 हज़ार 300 रुपए की आय हुई है।
- रायपुर ज़िले की 2 यूनिटों में अब तक सर्वाधिक 11 हज़ार लीटर, कांकेर में 7768 लीटर, दुर्ग में 2900, बालोद में 700, कोरबा में 284, कोरिया में 800, कोण्डागाँव में 2608, दंतेवाड़ा में 1443, बीजापुर में 800, बेमेतरा में 300, सूरजपुर में 500 एवं बस्तर में 1160 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन हुआ है। उत्पादित पेंट का विक्रय भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ई-लाईब्रेरी का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई-लाईब्रेरी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- ई-लाईब्रेरी के माध्यम से सरगुजा से बस्तर तक 33 ज़िलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में अध्ययनरत 27,000 छात्र-छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाईन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्मित ई-लाईब्रेरी के जरिये आगामी 7 वर्षों तक ये किताबें विद्यार्थियों के मोबाइल और लैपटॉप पर उपलब्ध रहेंगी।
- आगामी 4 वर्षों में लगभग 60,000 विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ कभी भी-कहीं भी अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ले सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास राज्य के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक होगा, तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित करेगा।

नोट :

मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोज़गारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 80 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। इससे आई.टी.आई. संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणापत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिये गए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देगा।
- छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवाँ सत्र मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करन का निर्णय लिया गया।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।
- औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिये पंजीयन की तिथि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई है।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि का किया अंतरण

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन जारी की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के हितग्राहियों को अब तक 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही इस योजना के शुरू होने से अब तक कुल 105 लाख 63 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में गोबर विक्रेताओं को 4.76 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद अब तक 211.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है।
- अंतरित की जा रही कुल राशि में से 76 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर खरीदी के एवज में की गई। इसमें से 2.06 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग द्वारा और 2.70 करोड़ रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों द्वारा भुगतान की गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 10 हज़ार 732 गौठान स्वीकृत किये गए हैं, जिसमें से 09 हज़ार 720 निर्मित होकर संचालित हो रहे हैं तथा शेष गौठानों का निर्माण तेजी से चल रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पिछले एक साल में लाभान्वित पशुपालकों की संख्या में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोबर खरीदी में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना से 3 लाख 28 हज़ार ग्रामीण पशुपालक लाभान्वित हुए हैं।
- राज्य में अब तक 5064 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 19 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से पेंट बनाने के लिये 21 ज़िलों में 45 इकाई स्वीकृत हुई हैं, इनमें से 13 इकाईयाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। शेष 32 यूनिट का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। अभी तक 30 हज़ार 218 लीटर पेंट का उत्पादन हो चुका है। इनमें से 14 हज़ार 358 लीटर पेंट का विक्रय हो चुका है। इससे 29 लाख 16 हज़ार 300 रुपए की आय प्राप्त हुई है।
- उन्होंने कहा कि 99 गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। अभी तक 01 लाख 33 हज़ार 484 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। इसका मूल्य 05 लाख 37 हज़ार 936 रुपए है। गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र कीट नियंत्रक और जीवामृत वृद्धि वर्धक के निर्माण तथा विक्रय से अब तक 28 लाख 96 हज़ार 845 रुपए की आय हो चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रही है। आज की स्थिति में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय अपनी पूंजी से कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट'व ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल 'एस.डी.जी. डैशबोर्ड'का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिये तैयार की गई 'छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021' का विमोचन किया एवं ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल 'एस.डी.जी. डैशबोर्ड' लांच किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एस.डी.जी. लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। 'जनघोषणा पत्र'के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप 'अंत्योदय'का संकल्प सम्मिलित है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई 'छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021' व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गए 'एस.डी.जी. डैशबोर्ड'में प्रत्येक ज़िले को 'स्कोर'एवं 'रैंकिंग'प्रदान की गई है।

नोट :

- 'स्कोर'एवं 'रैंकिंग'ज़िलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा और सभी कलेक्टरों को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा।
- यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड प्रत्येक ज़िला एवं विभाग को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी।
- समस्त ज़िला कलेक्टर रिपोर्ट व डैशबोर्ड में उल्लेखित इंडिकेटर संबंधित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण व अनुशीलन तथा डाटा संकलन एवं रिर्पोटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में 'ज़िला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति' गठित की गई है। इस समिति में संयोजक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत एवं सह-संयोजक, ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी हैं।
- रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर ज़िलों को 'स्कोर' व 'रैंकिंग'प्रदान की गई है।
- प्रत्येक एस.डी.जी. इंडिकेटर हेतु उत्तरदायी विभागों व ज़िला स्तरीय अधिकारियों को मैप किया गया है, साथ ही प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित योजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है।
- ज़िलों को उनके द्वारा अर्जित किये 'स्कोर'के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफॉर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 ज़िले - फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर) तथा शेष ज़िले- परफॉर्मर श्रेणी में हैं। ज़िला धमतरी ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल किया है।
- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखत: एसडीजी के साथ परस्पर जुडे हुए हैं। रिपोर्ट व डैशबोर्ड एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिये आँकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करती है।
- डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है। ज़िला स्तर पर बेहतर प्रसार हेतु एस.डी.जी. संबंधित 'हिन्दी पुस्तिका' भी जारी की गई है।

स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा आन-डिमांड बहु-भाषा शिक्षण पर आनलाईन कोर्स का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ज़िला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के लिये ऑनलाईन डिमांड बहु-भाषा शिक्षण हेतु ऑनलाईन कोर्स का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य में भाषायी सर्वे के आधार पर बच्चों को बहु-भाषा शिक्षण देने के लिये शिक्षकों के लिये पठन सामग्री का विमोचन किया। साथ ही बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में कहानी सुनाने के लिये पॉडकास्ट का उपयोग करने हेतु शिक्षकों का ऑन डिमांड क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में स्कूली बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की घोषणा की गई है, जिसके आधार पर मातृभाषा शिक्षण पर विभिन्न कार्य प्रारंभ किये गए हैं, इसका लाभ राज्य में आदिवासी अंचल के बच्चों को मिल रहा है।
- छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एल.एल.एफ.) और यूनिसेफ के सहयोग से भाषायी सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा किया गया है। ऐसे में अब जब कक्षाओं में बच्चों को सीखने में स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाना है, तो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिये ऑनलाईन कोर्स का शुभारंभ किया गया है।
- छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर आधारित भाषायी सर्वे किया है। इस रिपोर्ट को समझने एवं स्कूलों में शिक्षकों को बहुभाषा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने हुए शिक्षण विधियों में आवश्यक सुधार लाने हेतु समग्र शिक्षा की ओर से संदर्भ सामग्री तैयार की गई है। यह सामग्री प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

नोट :

- राज्य में वर्तमान में शिक्षकों की एक टीम द्वारा प्रतिमाह चर्चा पत्र को पॉडकास्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिसे शिक्षक बड़ी रूचि से सुनते हैं और उसमें कही गई बातों को अपनी-अपनी कक्षा में लागू करने का प्रयास करते हैं।
- इसी कड़ी में कुछ विशेषज्ञ शिक्षकों, कुछ स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षकों एवं कुछ बाह्य संस्थाएँ जो इस कार्य में सहयोग देना चाहते हों, उनके साथ मिलकर विभिन्न स्थानीय कहानियों का संकलन, उन पर पॉडकास्ट बनाना, बाद में चयनित कुछ कहानियों का प्रिंट वर्जन भी साझा करना जैसे कार्य इस टीम के साथ मिलकर किये जाएंगे।
- इस कार्य के लिये इच्छुक लोगों की टीम सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई जाएगी। इन पॉडकास्ट को स्कूलों में शिक्षकों द्वारा मोबाइल, प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध स्पीकर आदि का उपयोग कर इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। इस पॉडकास्ट को सुनकर बच्चे अपने संस्कृति, इतिहास एवं परंपराओं को जानकार आत्म गौरवान्वित हो सकेंगे।
- पॉडकास्ट निर्माण में तकनीकी समर्थन, इनके कक्षाओं में उपयोग हेतु उपकरण की आवश्यकता के आधार पर मांग एवं समर्थन हेतु 'विद्यांजली'पोर्टल पर भी इसे अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिये ज़िला ग्रंथालय के ई-लाइब्रेरी में 18 लाख रुपए की लागत से बनेगा ई-लाइब्रेरी क्लासरूम

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव ज़िले के कलेक्टर डोमन सिंह ने राजनांदगाँव ज़िले में अपने नित्य नए-नए प्रयोग करने की कड़ी में ज़िला ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से ज़िला ग्रंथालय लाइव के प्रथम तल पर 18 लाख रुपए की लागत से ई-लाइब्रेरी क्लासरूम बनाने की स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि ई-लाइब्रेरी क्लासरूम बन जाने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी।
- ई-लाइब्रेरी क्लास रूम के माध्यम से पीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।
- लाइब्रेरी का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा।

क्रेडा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था एन.आर.डी.सी के साथ किया एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने अमेरिका स्थित एनआरडीसी (NRDC) के ग्लोबल हेड एवं एडमिनेसट्रेटीव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.) के मध्य दिल्ली में एक करारनामा (एम.ओ.यू.) किया।

प्रमुख बिंदु

- क्रेडा ने प्रदेश में निर्मित भवनों में ऊर्जा दक्षता और कूल रूफ संबंधी तकनीक को साझा करने तथा इस क्षेत्र में प्रदेश के संबंधित विभागों, संस्थानों, तकनीकी व्यक्तियों, रियल इस्टेट कंपनियों आदि की इस विषय पर दक्षता निर्माण करने हेतु ए.एस.सी.आई. के एम.ओ.यू. किया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक कटियार ने इस करारनामा में हस्ताक्षर किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भवनों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने एवं उसकी गति बढ़ाने के लिये तकनीकी सहयोग एवं सलाह दी जाएगी, जिसके लिये कोई भी धनराशि नहीं प्रदान करनी होगी।
- इस प्रायोजन हेतु वर्कशॉप सेमीनार ट्रेनिंग विषय विषेशज्ञों का भ्रमण आदि क्रियाकलाप एन.आर.डी.सी. के द्वारा आयोजित किये जाएंगे। एन.आर.डी.सी. के द्वारा एनर्जी एफीसियेनशी बिल्डिंग कोड़ (ई.सी.बी.सी.) एवं कूल रूफ प्रोग्राम को छत्तीसगढ़ में लागू करने एवं तकनीकी सुविधा तथा प्रदर्शन उपलब्ध कराने का काम करेगी।

नोट :

- प्रदेश में ऊर्जा दक्ष व्यावसायिक भवनों का निर्माण छत्तीसगढ़ ईसीबीसी (CGECBC) के अंतर्गत किया जाएगा। इस हेतु सीजीईसीबीसी (CGECBC) कोड को पालन करने वाले ऊर्जा दक्ष भवनों के डिजाइन तैयार करने एवं निर्माण हेतु तथा भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ साथ भवन निर्माण के दौरान और निर्मित हो जाने के पश्चात् छत्तीसगढ़ ईसीबीसी के पालन की पुष्टि हेतु थर्ड पार्टी ऐसेसर इकाईयों को प्रशिक्षण दे कर प्रदेश में ही इस क्षमता का निर्माण किया जा सकेगा।
- हैदराबाद में स्थित एडमिनेसट्रेटीव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई) जिसने तेलंगाना व देश के अन्य प्रदेशों में ऊर्जा दक्ष भवनों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का महती कार्य किया है। इनके सहयोग से छत्तीसगढ़ में भी ये क्षमता निर्माण संभव होगा। इससे प्रदेश में ही उपलब्ध तकनीकी अमले को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। आने वाले समय में इससे प्रदेश में रोज़गार की नई संभावनाओं का उदय होगा।
- उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी) एक संयुक्त राज्य आधारित गैर-प्रॉफिट इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल एडवोकेसी ग्रुप है जिसका मुख्यालय न्यूयार्क में स्थित है। 1970 में स्थापित इस संस्था के तीन मिलियन से अधिक सदस्य है, जिनमें राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन गतिविधियाँ और लगभग 700 वकीलों, वैज्ञानिक और अन्य नीति विशेषज्ञ शामिल हैं।
- एनआरडीसी पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा संरक्षण विषयों पर जलवायु परिवर्तन के कार्यक्षेत्र में संलग्न एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।

छत्तीसगढ़ के दो अस्पतालों को 'मुस्कान' कार्यक्रम के अंतर्गत मिला एनक्यूएएस प्रमाण पत्र

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को 'मुस्कान' कार्यक्रम के तहत बच्चों और नवजातों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा तथा उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले दुर्ग ज़िला चिकित्सालय एवं पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत दिसंबर माह में ज़िला चिकित्सालय दुर्ग का और इस साल जनवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन का निरीक्षण कर इन दोनों अस्पतालों में बच्चों व नवजातों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में वहाँ इलाज कराने वालों से भी फीडबैक लिया था।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में ज़िला अस्पताल दुर्ग को 97 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को 84 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।
- टीम ने दुर्ग ज़िला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, एसएनसीयू और एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) का परीक्षण किया। वहीं उन्होंने पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीडियाट्रिक ओपीडी और एनबीएसयू (Newborn Stabilization Unit) का निरीक्षण कर मूल्यांकन किया।
- उल्लेखनीय है कि अस्पतालों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन 12 मानकों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है।
- इसके लिये संस्था द्वारा सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल सर्विसेस, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेस, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कोंडागाँव के कोकोड़ी में ले रहा आकार

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोंडागाँव ज़िले के कोकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनाल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जून 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार कोंडागाँव ज़िले में 140 करोड़ रुपए लागत से राज्य सरकार के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में यह पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोंडागाँव ज़िले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
- यह प्लांट कोंडागाँव में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिये फायदेमंद साबित होगा। ग्राम कोकोड़ी में 14 एकड़ शासकीय भूमि पर तैयार हो रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा।
- प्लांट में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन मक्का की प्रोसेसिंग होगी, जिससे 80 हज़ार लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इस प्लांट के लग जाने से निजी निवेशकों द्वारा अन्य सहायक उद्योग लगाने के लिये नया वातावरण बनेगा।
- प्लांट में उत्पादित होने वाला एथेनॉल का विक्रय इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को किया जाएगा, जिसे पेट्रोल के साथ मिक्स कर बेचा जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी साथ ही किसानों को मक्का का वाजिब दाम भी मिलेगा।
- मक्का प्रसंस्करण प्लांट ज़िले के मक्का उत्पादक किसानों की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा। इससे करीब 45 हज़ार से ज्यादा किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही समीपस्थ अन्य ज़िले के मक्का उत्पादक किसानों के मक्का का प्रसंस्करण किया जाएगा। मक्का प्रसंस्करण प्लांट में क्षेत्र के लगभग 200 से ज्यादा लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा।
- कोंडागाँव ज़िले में बीते तीन-चार सालों में खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला है। प्लांट की स्थापना से उत्साहित किसान मक्का का रकबा साल दर साल बढ़ा रहे है। वर्तमान में कोंडागाँव ज़िले में प्रति वर्ष 3 लाख 48 हज़ार 127 मेट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है।
- स्टेट प्रोजेक्ट फाईनेंस कमेटी द्वारा मक्का से एथेनॉल निर्माण के लिये प्रोसेसिंग प्लांट को फिजीबल पाया गया था। लगभग 140 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट के निर्माण में किसानों ने 7.06 करोड़ रुपए की अंश पूंजी का योगदान दिया है। इसी प्रकार मंडी बोर्ड द्वारा 21.19 करोड़ रुपए और राज्य शासन द्वारा 35.32 करोड़ रुपए तथा सहकारी संस्था के स्वयं की निधि से 2.10 करोड़ रुपए दिये हैं। शेष 75 करोड़ रुपए बैंक ऋण के माध्यम से जुटाए गए हैं।
- कोंडागाँव ज़िले में समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिये 47 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। ज़िले के कोंडागाँव माकड़ी, फरसगाँव, बड़ेराजपुर विकासखंड में मक्के का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मक्का खरीदी का कार्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है।
- मक्का उत्पादक किसानों को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।
- कोंडागाँव ज़िले में खरीफ सीजन में एक लाख 24 हज़ार 188 तथा रबी सीजन में 2 लाख 23 हज़ार 929 टन मक्का का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन से ज़िले के लगभग 65 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को विशेष प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है।

प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में हुआ शुरू

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को कोरबा ज़िले के कलेक्टर संजीव झा और महापौर राज किशोर प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मौजूदगी में कोरबा शहर के निहारिका में स्मृति उद्यान के सामने ज़िले का पहला और प्रदेश के दूसरे मिलेट कैफे का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि दुनियाभर में साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा में भी अब ज़िले के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत हो गई है। इस कैफे में सेहत के लिये भरपूर मिलेट्स के व्यंजन का स्वाद लोग ले सकेंगे।
- कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार कोरबा ज़िले में पहले मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया गया है। यह कैफे रायगढ़ ज़िले के बाद प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफे है।
- इस मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी ,रागी समेत अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित व्यंजन जैसे इडली, डोसा, पोहा, उपमा, भजिया खीर, हलवा, कुकीज, मोल्ड के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन लोगों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

नोट :

- कोरबा के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत ज़िला प्रशासन की पहल व सहयोग से हुआ है। इसका संचालन नव जागृति महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इससे महिला स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को भी फायदा भी होगा।
- उल्लेखनीय है कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और इनसे मिलने वाले पोषक तत्त्वों के बारे में जन जागरूकता के लिये वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से कोदो, कुटकी और रागी की खेती होती है। इसके उत्पादन को मिल रहे प्रोत्साहन से किसानों का भी उत्साह बढ़ा है।

विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की ली शपथ

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के नौवें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अनुसुइया उइके का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
- ओडिशा के रहने वाले 84 वर्षीय हरिचंदन ओडिशा के भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक और चार बार मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक वे जनसंघ के आंध्र महासचिव रहे।
- हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे। साल 1980 से 1988 तक वे बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। वह 1996 से 2009 के बीच 13 साल तक ओडिशा विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी रहे। उन्होंने 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया।

डॉ. ममता चंद्राकर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉ. मोक्षदा (ममता) चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित से किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साल 2019, 2020 और 2021 के लिये संगीत नाटक अकादमी की फैलोशिप (अकादमी रत्न) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्रदान किये।
- विदित है कि संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने गत 6-8 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दस (10) प्रतिष्ठित विभूतियों को अकादमी अध्येता (फेलो) के रूप में चुना है।
- अकादमी की फैलोशिप एक सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, जो किसी भी समय 40 तक सीमित है। इन दस (10) अध्येताओं के चयन के साथ ही वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अब 39 अध्येता हो गए हैं।
- सामान्य परिषद ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 हेतु अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत संगीत नाटक के लिये संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/रंगमंच, कठपुतली कला और प्रदर्शन कला में समग्र योगदान/छात्रवृत्ति के लिये के क्षेत्र से एक सौ अट्ठाईस (128) कलाकारों का चयन किया था। इन एक सौ अट्ठाईस (128) कलाकारों में तीन संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं।
- देश-विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली ममता चंद्राकर खैरागढ़ को 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता चंद्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। वे 2016 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री से और 2013 छत्तीसगढ़ रत्न में अलंकृत की गईं।

नोट :

- संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिये भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। 1952 में (तत्कालीन) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉ. पी.वी. राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
- यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है।
- अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों और परियोजनाओं की स्थापना करती है। कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं:
  - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली 1959 में।
  - जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल- 1954 में।
  - कथक केंद्र (राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान), नई दिल्ली- 1964 में।
  - कुटियाटेम (केरल का संस्कृत थिएटर), पूर्वी भारत के छऊ नृत्य, असम की सत्रिया परंपरा आदि के समर्थन की राष्ट्रीय परियोजनाएँ।
- संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न):
  - संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
  - अकादमी की फैलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है, जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दी जा सकती है।
  - अकादमी फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है।
- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) :
  - संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान/छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को पुरस्कार दिये जाते हैं।
  - अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल होता है।

'दिशा' स्कीम के तहत शार्ट फिल्म प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को भारत सरकार के न्याय विभाग एवं नालसा के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही 'दिशा' स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष की शार्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में स्थित आदिवासी बाहुल्य जगदलपुर नगर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता में 5 से 10 मिनट की अवधि की शार्ट फिल्में न्याय विभाग एवं नालसा की 'दिशा' स्कीम थीम पर तैयार कर 15 मार्च तक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- इस प्रतियोगिता में कोई भी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति, संगठन अथवा कोई भी संस्था भाग ले सकता है।
- इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
- इसके अलावा कानूनी जागरूकता से संबंधित अन्य शार्ट फिल्में (दिशा एवं अन्य विषयों पर) गैर-प्रतियोगिता वर्ग में जमा की जा सकती हैं, इनका भी प्रदर्शन किया जा सकेगा।
- ज्ञातव्य है कि 'दिशा' स्कीम के अंतर्गत मोबाईल एवं वीडियो के माध्यम से तथा जन सूचना केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किया जा रहा है तथा इसके लिये प्रत्येक ज़िले हेतु एक-एक टेली अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है।

राज्य के सभी रीपा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में बताया गया कि ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों यानि रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) मुंबई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिये ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि रीपा सेंटरों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहाँ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कई रीपा का निर्माण पूरा हो चुका है और वहाँ विभिन्न ग्रामीण उद्यम संचालित किये जा रहे हैं।
- अजय सिंह ने बताया कि राज्य योजना आयोग की इस बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केंद्रों की स्थापना तथा गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक व इकाइयों के विस्तार को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई।
- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- बैठक में बार्क के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण तकनीकी केंद्र में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोज़गार से जुड़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन केंद्रों में फल-सब्जी और वनोपजों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने की विधि एवं अन्य विधाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6 दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 6 दिवसीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री अनिला भेंड़िया ने इस अवसर पर नगर निगम की 100 स्वच्छता दीदियों का कैप और टी-शर्ट देकर सम्मान भी किया।
- महिला बाल विकास विभाग द्वारा बीटीआई ग्राउंड में आयोजित महिला मड़ई 4 मार्च तक चलेगी। यहाँ प्रदेश के 33 ज़िलों के महिला स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा स्व-निर्मित सामग्रियों के 66 स्टॉल की प्रदर्शनी लगी है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि इस मड़ई में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सशक्त होते कदमों और आत्मनिर्भर बनते जीवन की स्पष्ट झलक दिखाई देगी। इसके साथ महिला समूहों और उद्यमियों को प्लेटफार्म और नई पहचान मिलेगी।

21वाँ अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिसार (हरियाणा) में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता में छठवाँ स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं के अंतर्गत दो स्वर्ण, एक रजत तथा एक काँस्य पदक अर्जित किया।
- इस प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि महाविद्यालय रायपुर के एम.एस.सी. एग्रोनॉमी के छात्र विजय कुमार ने लंबी कूद स्पर्धा में तथा एम.एस.सी. कृषि मौसम विज्ञान विभाग के छात्र समीर कैमरों ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।
- इसी प्रकार लंबी कूद महिला स्पर्धा में कृषि महाविद्यालय बेमेतरा की छात्रा नीलावती नाग ने रजत पदक तथा 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में कृषि महाविद्यालय राजनांदगाँव के छात्र राजेश कुमार सोरी ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस वर्ष हिसार (हरियाणा) में 20 से 24 फरवरी तक 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 66 कृषि विश्वविद्यालय की टीमें शामिल हुई थीं।

नोट :